

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-305/2016

शीशराम

—अपीलार्थी

बनाम

1. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, झुंझुनू।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, झुंझुनू।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.07.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर, अधिवक्ता  
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)  
शुचि शर्मा, सदस्य

## आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 16.10.1985 के द्वारा अस्थाई तौर पर अध्यापक ग्रेड—तृतीय के पद पर हुई थी। अपीलार्थी को पंचायत समिति द्वारा आदेश दिनांक 30.08.1991 के द्वारा नियुक्ति तिथि से स्थाई करने के आदेश दिये गये। अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ नियुक्ति की दिनांक 01.07.1986 मानते हुए 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.07.1995 से दिया गया। अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ नियुक्ति की दिनांक 12.08.1989 मानते हुए दिनांक 12.08.2007 से प्रदान किया गया, जबकि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति की दिनांक 01.07.1986 से गणना करते हुए 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए था। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी के संबंध में पारित आदेश दिनांक 01.11.2011 अपास्त किया जाए, जिसके द्वारा अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ सेवा की गणना दिनांक 12.08.1989 से मानते हुए दिया गया है। अपीलार्थी ने यह भी प्रार्थना की है कि अपीलार्थी की नियुक्ति की दिनांक 01.07.1986 से सेवा की गणना करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाए।
2. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
3. अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 16.10.1985 के द्वारा हुई थी, वह पूर्णतः अस्थाई तौर पर हुई थी। अपीलार्थी ने अपनी अपील में यह तथ्य अंकित

किये हैं कि सलेक्शन कमेटी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 12.08.1989 से नियमित माना है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशल रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं पर अपना निर्णय दिया है:—

- "(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?
- (b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?
- (c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?
- (d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?
- (e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :—

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc

period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

4. हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी की सेवाएं सलेक्शन कमेटी द्वारा चयन के पश्चात ही नियमित की गयी है। उससे पूर्व की सेवा तदर्थ रूप में दी गयी थी। नियमितिकरण की दिनांक से ही अपीलार्थी की सेवाएं नियमित मानी जा सकती है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि नियमितिकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवाएं मानी जानी चाहिए। यह भी माना है कि चयनित वेतनमान एवं अन्य लाभों के सम्बन्ध में नियमितिकरण की दो भिन्न तारीखे नहीं हो सकती। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की जो सेवाएं सलेक्शन कमेटी द्वारा चयन के बाद नियमित की गयी है, उससे पूर्व की सेवा को अपीलार्थी एसीपी एवं अन्य लाभों के लिये अपनी सेवा में नहीं जुड़वा सकता है।
5. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)  
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)  
सदस्य (न्यायिक)